भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †2784

उत्तर देने की तारीख- 12/12/2024

ओडिशा में पीएम-जनमन योजना

†2784. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओडिशा के डोंगरिया कोंध और बोंडा जैसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) कुपोषण, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा और अवसंरचना की कमी का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ओडिशा के पीवीटीजी के उक्त मुद्दों के समाधान के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) योजना के तहत क्या विशिष्ट हस्तक्षेप किए गए हैं और क्या प्रगति हुई है;

(ग) ओडिशा में पीएम-जनमन योजना के कार्यान्वयन में किसी भी देरी या अंतराल के क्या कारण हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएम-जनमन योजना के तहत ओडिशा के पीवीटीजी के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (घ): चूंकि ओडिशा में डोंगरिया कोंध और बोंडो सहित पीवीटीजी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में भेद्यता (अरक्षितता) का सामना कर रहे थे, इसलिए 15 नवंबर 2023 को, माननीय प्रधानमंत्री ने ओडिशा सहित 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) का शुभारंभ किया। इस मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और शिक्षा तक बेहतर पहुंच, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9-संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा करने की योजना बनाई गई है। ओडिशा में अभियान योजना के तहत इसकी शुरुआत से लेकर अब तक दिए गए लाभों का ब्यौरा, मंत्रालय-वार, **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। मिशन के तहत किए गए उपायों के अवलोकन से पता चलता है कि ओडिशा सहित सभी पीवीटीजी के लिए आंगनवाड़ी, सचल चिकित्सा इकाई (मोबाइल मेडिकल यूनिट) और सड़क निर्माण आदि की स्थापना के माध्यम से मिशन के तहत कुपोषण, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा और अवसंरचना संबंधी कमियों का भी ध्यान रखा जा रहा है।

मिशन के तहत बजट 24,104 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है और यह मिशन 31.3.2026 को समाप्त होने वाली अवधि तक है। 21.11.2024 तक जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अभियान के तहत 8369.87 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय अभियान के लिए नोडल मंत्रालय है। हालांकि, प्रत्येक मंत्रालय को अभियान के तहत बजट और लक्ष्य आवंटित किए गए हैं और वह उसे सौंपे गए उपाय को क्रियान्वित (लागू) करने के लिए जिम्मेदार है। आज तक, ओडिशा में पीएम जनमन के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी या अंतरों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस मंत्रालय के संज्ञान में नहीं लाया गया है।

अनुलग्नक-I

"ओडिशा में पीएम-जनमन योजना" के संबंध में श्री सप्तगिरी शंकर उलाका द्वारा दिनांक 12.12.2024 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या †2784 के भाग (क) से (घ) के उत्तर के संबंध में संदर्भित अनुलग्नक

ओडिशा में पीएम जनमन के तहत दिए गए लाभों* का विवरण (21.11.2024 तक)

मंत्रालय	उपाय	स्वीकृतियां	वित्तीय स्वीकृतियाँ (करोड़ रुपए में)
ग्रामीण विकास मंत्रालय	पक्के मकान	28757 मकान	263.72
	संपर्क सड़कें	147.87 किमी सड़क	149.75
जल शक्ति मंत्रालय	पाइप से जलापूर्ति	525 गांव संतृप्त	उपलब्ध नहीं है
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू)	50 एमएमयू स्वीकृत	16.94
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी)	90 एडब्ल्यूसी	14.64
शिक्षा मंत्रालय	छात्रावास	30 छात्रावास	82.50
विद्युत मंत्रालय	आवासों (घरों) का विद्युतीकरण	1326 आवास	0**
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	आवासों (घरों) का विद्युतीकरण	-	-
दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय	मोबाइल टावर	130 बस्तियां	13.5
जनजातीय कार्य मंत्रालय	बहुउद्देशीय केंद्र (एमपीसी)	61 एमपीसी	24.64
	वीडीवीके की स्थापना	43 वीडीवीके	1.7765

*संबंधित मंत्रालयों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार

**विद्युत मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ओडिशा राज्य अपने राज्य की योजना के माध्यम से पीएम जनमन के तहत पीवीटीजी आवासों (घरों) के विद्युतीकरण कार्यों को क्रियान्वित कर रहा है।

*****